an>

Title: Need to set up a National Commission on Irrigation.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, इस सदन में हमेशा किसानों के बारे में बात होती है। किसान समस्या में हैं और उनकी आत्महत्या लगातार बढ़ रही है। हम उन्हें सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण जो परेशानी हो रही है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी बेमौसम बारिश होती है, जिसकी वजह से उनकी फसल क्षतिग्रस्त होती है। इस सदन में हमेशा चर्चा होती है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए। लेकिन किसान का लागत मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता है। कई किसान नहर से पानी ले रहे हैं, तो कई ट्यूबवैल्स द्वारा पानी ले रहे हैं और बिजली तथा डीजल से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जब-जब इस देश में अकाल आया, सन् 1901 में एक इरीगेशन कमीशन बना था। उसके बाद सन् 1967-1968 में जब पूरा किसान परेशान था, तो इरीगेशन कमीशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन राज्यों के बीच काफी समस्याएं थीं कि किसके पास कौन सा पानी जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। आज क्लाइमेट चेंज के कारण और किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा राज्यों के बीच डिस्प्यूट चल रहे हैं कि कहां डैम बनाना है कहां नहीं बनाना है। इस वजह से आज़ादी के इतने सालों के बावजूद भी हम किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह 1901 में और फिर 1969 में इरीगेशन कमीशन बने, आज फिर से 45-50 साल बाद उसकी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए और सरकार को एक नया इरीगेशन कमीशन बनाना चाहिए, जिससे हम सभी किसानों के खेतों में पानी मुहैया करा सकें।

माननीय अध्यक्ष:

श्री पी.पी. चौधरी,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।